सीमा-शुल्क आयकर विभागों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना

2465. **श्रीमती वीणा वर्मा :**

श्री राम चन्द्र विकल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, आयकर विभागों और प्रवर्त्तन निदेशालय के उन कर्मचारियों को जो वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने में लगे हुए हैं इनाम देने की कोई प्रोत्साहन योजना लागू की है ; और

(ख) यदि हां तो उपयुक्त अवधि के दौरान उस योजना के अधीन दिये गये पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हां ।

(ख) आय कर प्राधिकारियों ने 743 मामलों में पुरस्कार प्रदान किये तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण तथा नारकोटिक प्राधिकारियों ने 7321 मामलों में पुरस्कार प्रदान किये । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भी 814 मामलों में पुरस्कार दिए गए थे ।

Smuggling of Synthetic Textiles

2466. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Mini ter of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large scale smuggling of synthetic textiles has adversely affected the power-loom and mill sectors of the textile industry;

(b) what were the wholesale prices of smuggled Boski 45 variety, suiting, 54 and sarees and the prices of comparable Indian varieties; and

(c) whether his Ministry has recom mended to the Ministry of Finance to reconsider its excise policy in regard to PFV and other raw materials used in the production of -ynthetic textiles, and if so, what is the response thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) While Government are aware that there is some smuggling of synthetic textiles, it is not possible to give precise figures of the quantum of prices of smuggled goods.

(b) The price, of Indian varieties of cloth are given in the statement attached. *(.See* below)

(c) The Textile Policy in June, 1985, states that fiscal levies on man-made fibres/yarn and on intermediates used as inputs for the production of such fibres| yarn fshall be progressively reduced in such a manner as to facilitate absorption of increased domestic production, so that the benefit flows to the consumer in the form of lower prices of synthetic and blended fabrics. However, details of specific proposals regarding changes in excise duties sent to the Finance Ministry are not disclosed before a final decision is taken thereon..

Statement

Ex-Mill prices of Mill-made Fabrics as on September, 1987 (Rs. per mtr.)

1, Suitings (132—137 cms.) (avg. of 7 varieties)	50-38
2; Shirtings (89—91 cms.) Poplins, (avg. of 9 varieties)	22 00
3. Sarees (Avg. of 6 varieties).....	*24-60*

Month End Market Prices of Fah ics

(Rs. per wtr.)

Texo Bosky 47"	*September 1987*
76x76(5-5 kgs.) printed	1410
Dyed	1500
China Bosky	
44x76(5.5 kgs.) .	12-00
44x76 (7.0 kgs.) .	15.00 -
Saree Cloth (49")	
60s (67/33)x76D Texturised 88x76	10-65

Loans for setting up industries

2467. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of FINANCE he pleased to state:

(a) the number of loans sanctioned by the Central Government to industrialists for setting up industries and factories during the last three years, State-wise, and the amounts sanctioned;

(b) the number of industries and factories set up by them during this period;

(c) the amount towards loan repaid by the loanees, State-wise, till October 1987; and

(d) the steps taken by Government to recover the loans' from those who have falied to repay the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POGJARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House to the extent availab'e and permissible under the rules.

ग्वालियर स्थित जियाजी काटन मिल्स के कतिपय विभागों में काम का बन्द होना।

2468. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री अजीत जोगी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर स्थित जियाजी काटन मिल्स के प्रबंधकों ने मिल के कुछ विभागों में काम बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मजदूर कार्यमुक्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जियाजी काटन मिल्स लि०ग्वालियर ने मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसा आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 414 पुराने सादे करघों और अनुषंगी विभागों के कार्य चालन को निलम्बित करने के लिये औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अधीन अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने इस आवेदन-पत्र का निपटान करते हुए मिल के प्रबन्ध-मण्डल को निर्देश दिये कि प्रभावित कामगारों के लिये एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना तैयार की जाये । स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना क्रियान्वित हो रही है । किसी भी कामगार को जबरन बेरोजगार नहीं किया गया है ।